

UPSC (IAS) Prelims 2025

Current Affairs

18 Months

CRASH

COURSE

#IAS

ABHAY SIR



Events in News



- महामारी निधि परियोजना
- डायरेक्ट-टू-डिवाइस (D2D) सैटेलाइट कनेक्टिविटी
- वन नेशन, वन सब्सक्रिप्शन योजना
- भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंध
- भगवान बिरसा मुंडा



Prof. S P Singh Baghel
Hon'ble Minister of State for Fisheries.

Shri. Rajiv Ranjan Singh
Alias Lalat Singh
Hon'ble Minister of Fisheries, Animal
Husbandry and Poultry

Shri. George Kurian
Hon'ble Minister of State for Fisheries
and Aquaculture

महामारी निधि परियोजना

महामारी निधि परियोजना



Daily Current News

- महामारी निधि परियोजना
- भारत में "महामारी से निपटने की तैयारी और प्रतिक्रिया के लिए पशु स्वास्थ्य सुरक्षा सुदृढीकरण" पर केंद्रित महामारी निधि परियोजना की शुरुआत की गई है।
- इसका मुख्य उद्देश्य पशुओं में होने वाली बीमारियों से समय रहते निपटना और इंसानों तक संक्रमण फैलने से रोकना है।



महामारी निधि परियोजना



Daily Current News

- परियोजना के बारे में मुख्य बातें:
- कौन दे रहा है पैसा?
- यह परियोजना G-20 महामारी निधि (G20 Pandemic Fund) के तहत चलाई जा रही है।
- इसके लिए भारत को 25 मिलियन डॉलर (लगभग 200 करोड़ रुपए) की सहायता मिली है।



महामारी निधि परियोजना



Daily Current News

- उद्देश्य क्या है?
- निम्न और मध्यम आय वाले देशों को मदद देना ताकि वे: पशु स्वास्थ्य से जुड़ी खतरनाक बीमारियों से बच सकें।
- महामारी जैसी स्थितियों का सामना करने के लिए तैयार हो सकें।



महामारी निधि परियोजना



Daily Current News

- कौन इसे लागू कर रहा है?
- विश्व बैंक (World Bank)
- एशियाई विकास बैंक (ADB)
- खाद्य और कृषि संगठन (FAO)





- पशु रोगों को गंभीरता से लेना क्यों ज़रूरी है?
- 1. इंसानों में संक्रमण फैलने से रोकने के लिए: WHO के अनुसार अब तक 6 वैश्विक स्वास्थ्य आपात स्थितियों में से 5 बीमारियाँ जानवरों से इंसानों में फैली थीं।
- जैसे – बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू आदि।





- 2. आर्थिक नुकसान से बचाव:
- SARS महामारी से दुनियाभर में 50 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ था।
- एवियन फ्लू से 30 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ।



महामारी निधि परियोजना



Daily Current News

- परियोजना के तहत होने वाली मुख्य पहलें:
- पशु प्रयोगशालाओं और वैक्सीन केंद्रों का अपग्रेड ताकि बीमारियों की पहचान और इलाज जल्दी हो सके।
- प्रारंभिक चेतावनी और निगरानी तंत्र को मजबूत करना जिससे बीमारी फैलने से पहले ही अलर्ट मिल जाए। डेटा और विश्लेषण तंत्र को बेहतर बनाना



महामारी निधि परियोजना



Daily Current News

- ताकि बीमारी के खतरे का अनुमान लगाया जा सके।
- आपदा प्रबंधन फ्रेमवर्क तैयार करना
- जिससे राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संस्थाएं आपस में समन्वय करके तुरंत कदम उठा सकें।



प्रश्न: निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. महामारी निधि (Pandemic Fund) को विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा स्थापित किया गया था।
2. इस निधि का उद्देश्य निम्न और मध्यम आय वाले देशों की महामारी की तैयारी और प्रतिक्रिया क्षमताओं को मजबूत करना है।
3. भारत इस फंड का प्राप्तकर्ता (beneficiary) देश है।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

- A. केवल 1
- B. केवल 2 और 3
- C. केवल 2
- D. 1, 2 और 3

उत्तर: C. केवल 2

स्पष्टीकरण:

कथन 1 गलत है: Pandemic Fund की स्थापना WHO ने नहीं, बल्कि विश्व बैंक (World Bank) ने की है, G20 के सहयोग से।

कथन 2 सही है: इसका उद्देश्य निम्न और मध्यम आय वाले देशों की महामारी की तैयारी, निगरानी, और त्वरित प्रतिक्रिया क्षमताओं को मजबूत करना है।

कथन 3 गलत है: भारत को इस निधि से प्रत्यक्ष फंडिंग प्राप्त नहीं हुई है, हालाँकि भारत इसमें एक साझेदार या योगदानकर्ता के रूप में शामिल हो सकता है।



डायरेक्ट-टू-डिवाइस (D2D) सैटेलाइट कनेक्टिविटी

डायरेक्ट-टू-डिवाइस सैटेलाइट कनेक्टिविटी



Daily Current News

- भारत की सरकारी टेलिकॉम कंपनी BSNL ने देश की पहली डायरेक्ट-टू-डिवाइस (D2D) सैटेलाइट कनेक्टिविटी सेवा शुरू की है।
- यह तकनीक अब आम लोगों को भी सीधे सैटेलाइट से मोबाइल पर नेटवर्क देने की दिशा में एक बड़ी पहल है।

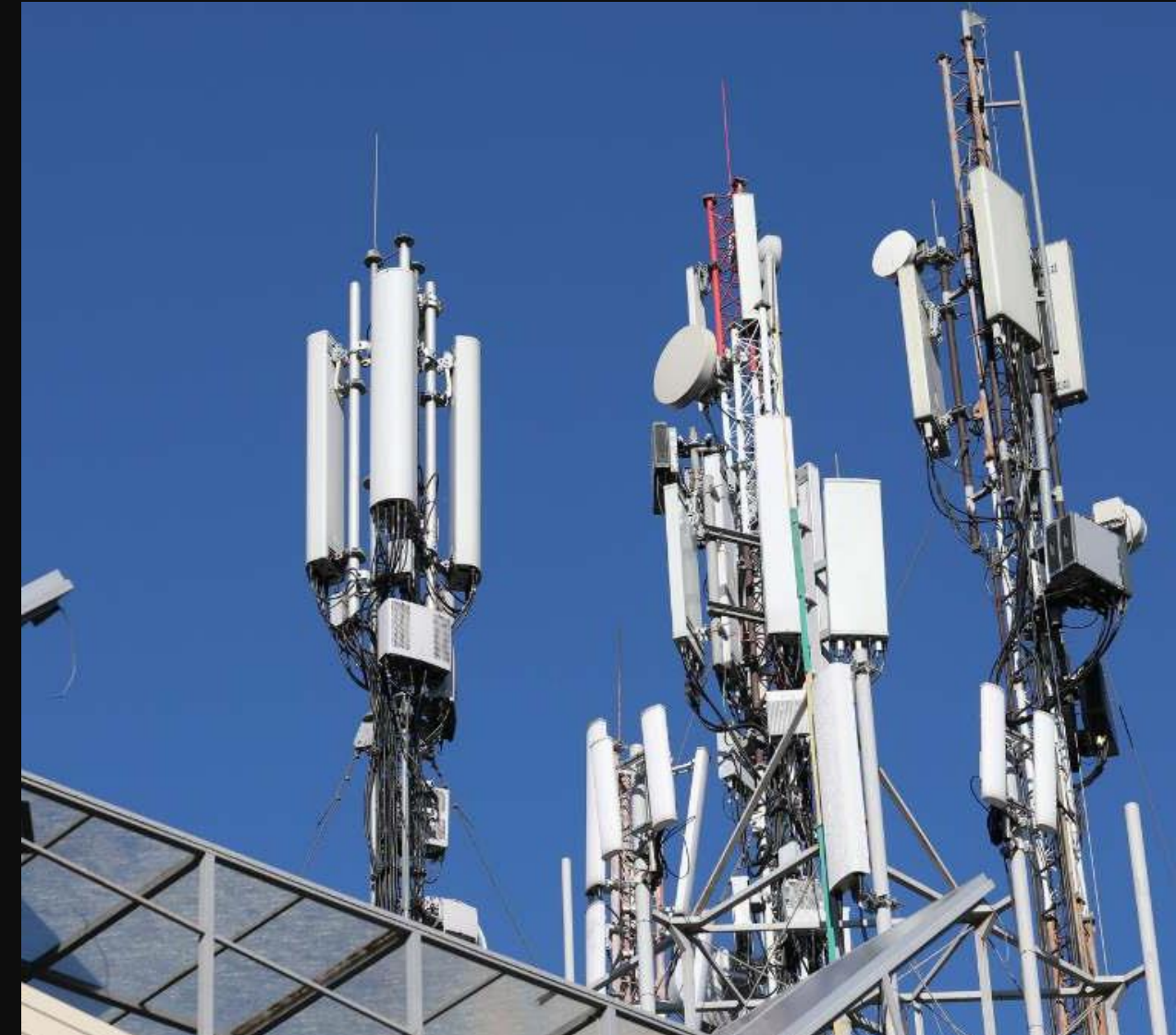


डायरेक्ट-टू-डिवाइस सैटेलाइट कनेक्टिविटी



Daily Current News

- यह तकनीक क्या करती है?
- सैटेलाइट = मोबाइल टॉवर अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट अब धरती पर लगे मोबाइल टॉवर्स की तरह काम करेंगे।
- इससे नेटवर्क के लिए ज़रूरी टॉवर की ज़रूरत कम हो जाएगी।

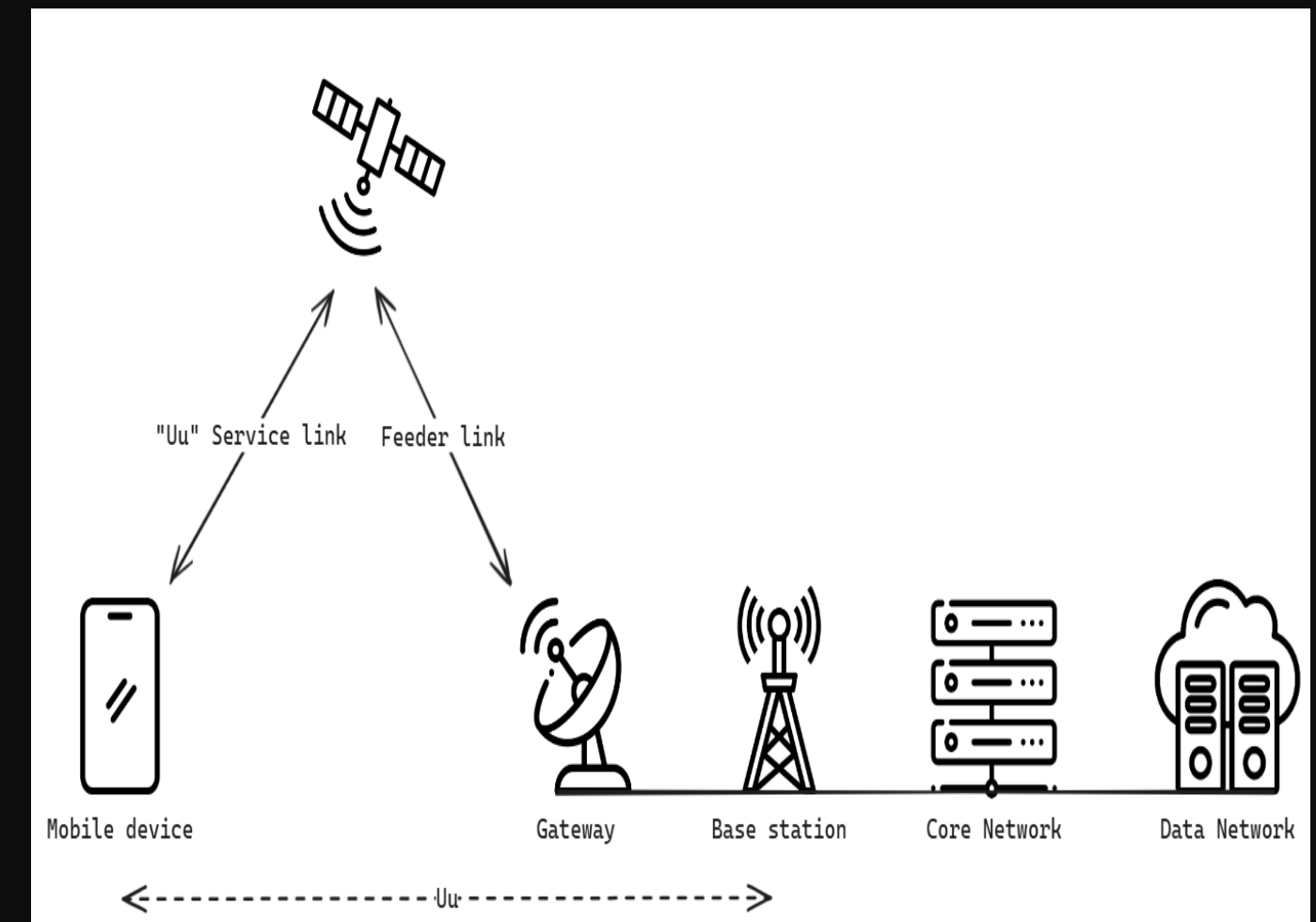


डायरेक्ट-टू-डिवाइस सैटेलाइट कनेक्टिविटी



Daily Current News

- सीधा मोबाइल से जुड़ाव
- यह तकनीक मोबाइल फोन को सीधे सैटेलाइट से जोड़ती है, बिना किसी अतिरिक्त उपकरण के।
- गैर-स्थलीय नेटवर्क (NTN) प्रौद्योगिकी यह दो-तरफा संवाद (टॉक और रिसीव) को सैटेलाइट और मोबाइल डिवाइस के बीच सीधे संभव बनाती है।



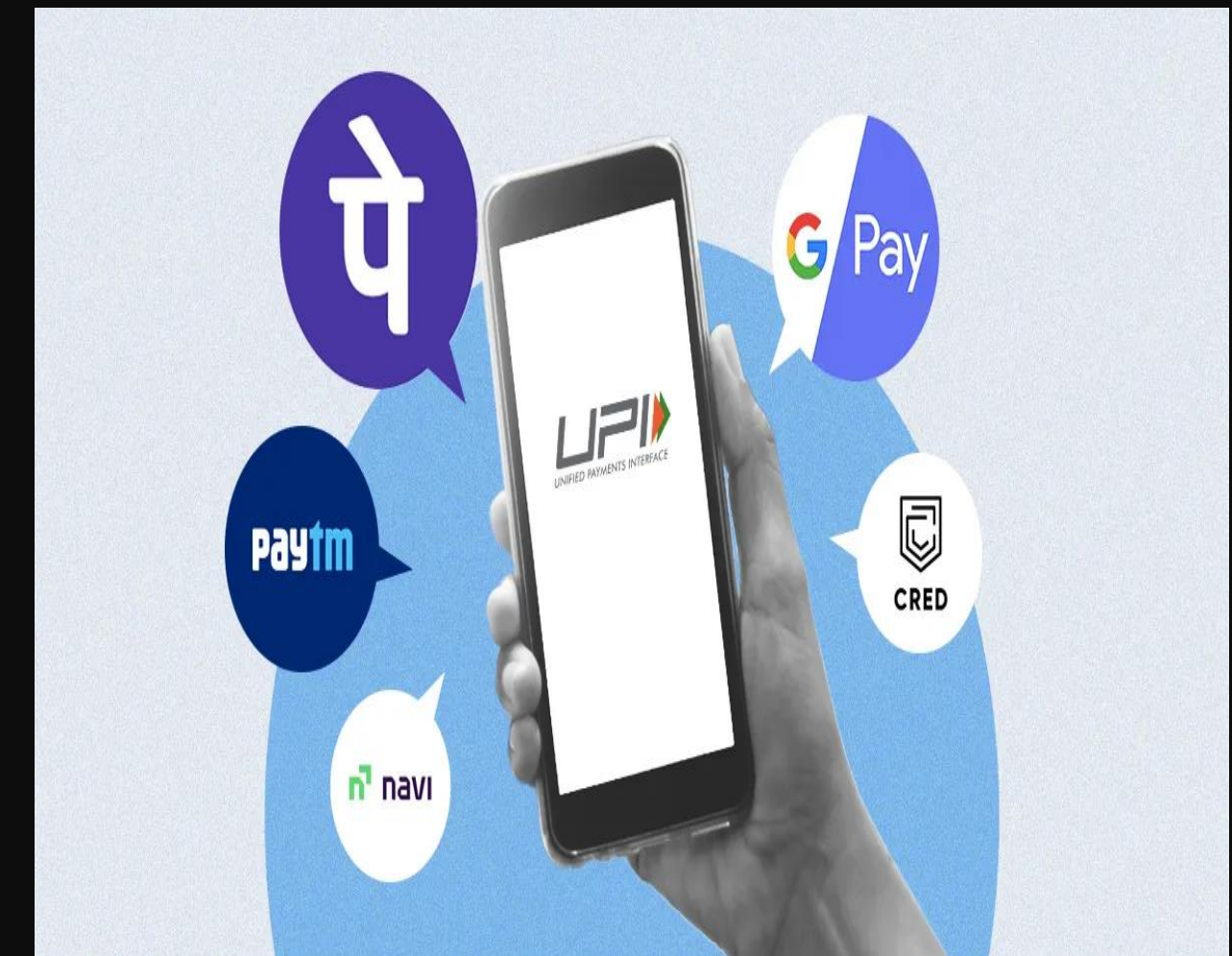


- **BSNL किस सैटेलाइट का उपयोग कर रहा है?**
- BSNL 36,000 किलोमीटर ऊपर स्थित जियोस्टेशनरी एल-बैंड सैटेलाइट (ViaSat) का उपयोग करेगा।
- इससे दूरदराज के क्षेत्रों में भी मोबाइल सिग्नल और इंटरनेट उपलब्ध हो सकेगा।





- इस तकनीक का महत्व क्या है?
- 1. हर मौसम में कनेक्टिविटी: चाहे बारिश हो या तूफान, नेटवर्क चलता रहेगा।
- 2. दूर-दराज़ इलाकों में इंटरनेट: जहां आज तक मोबाइल नेटवर्क नहीं पहुंचा, वहां भी हाई-स्पीड इंटरनेट मिलेगा।
- 3. UPI और डिजिटल लेन-देन संभव: गांवों और पहाड़ी इलाकों में भी ऑनलाइन भुगतान किया जा सकेगा।
- 4. आपातकालीन सेवाएं: जंगल, पहाड़ या समुद्र में फंसे लोगों के लिए कॉल और SOS मैसेज भेजना संभव होगा।



डायरेक्ट-टू-डिवाइस सैटेलाइट कनेक्टिविटी



Daily Current News

- दुनियाभर में कौन-कौन कर रहा है ऐसा?
- AST Space Mobile
- Lynk Global
- Constellation Global
- SpaceX – Starlink
- ये कंपनियां भी D2D टेक्नोलॉजी पर काम कर रही हैं।

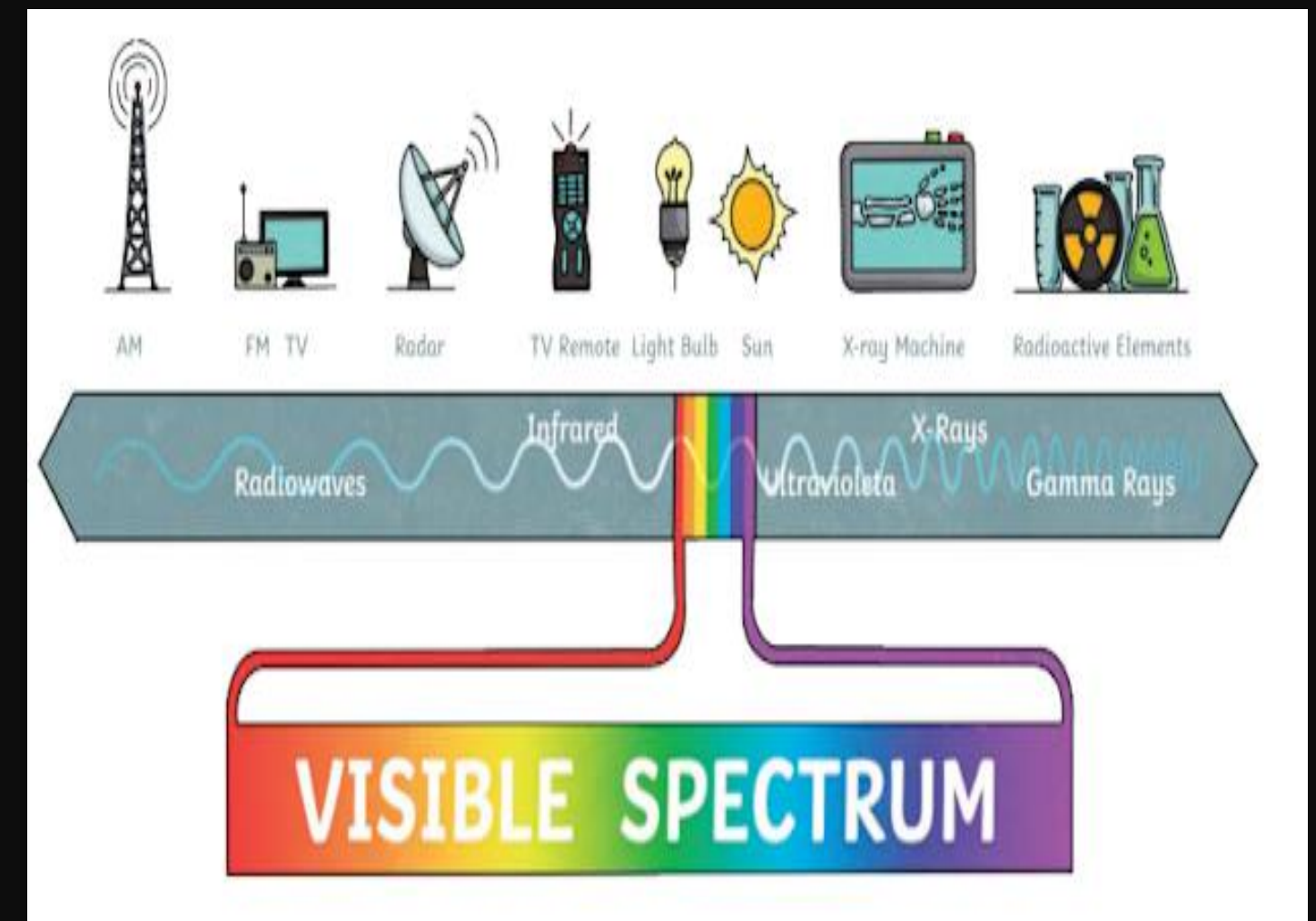


डायरेक्ट-टू-डिवाइस सैटेलाइट कनेक्टिविटी



Daily Current News

- चुनौतियाँ क्या हैं?
- 1. थोड़ा विलंब (Latency): वॉयस कॉल या लाइव वीडियो में थोड़ी देरी हो सकती है।
- 2. विनियामक दिक्कतें: चूंकि सैटेलाइट सीमाओं से परे हैं, तो कानूनों का पालन करना चुनौती बन सकता है।
- 3. स्पेक्ट्रम की कमी: सैटेलाइट संचार के लिए पर्याप्त फ्रीक्वेंसी बैंड मिलना मुश्किल हो सकता है।





- **4. स्मार्टफोन की संगतता:** सभी फोन इस तकनीक को सपोर्ट नहीं कर सकते।
- **5. सिग्नल की स्थिरता:** पहाड़ों, जंगलों या इमारतों के बीच सिग्नल में रुकावट आ सकती है।

प्रश्न: निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. डायरेक्ट-टू-डिवाइस सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के माध्यम से स्मार्टफोन बिना किसी ग्राउंड नेटवर्क के सीधे सैटेलाइट से कनेक्ट हो सकते हैं।
2. इस तकनीक के लिए विशेष सैटेलाइट-इनेबल्ड स्मार्टफोन की आवश्यकता होती है; सामान्य स्मार्टफोन इससे कनेक्ट नहीं हो सकते।
3. भारत में कुछ निजी कंपनियाँ इस तकनीक के लिए अंतरिक्ष स्टार्टअप्स के साथ साझेदारी कर रही हैं।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

- A. केवल 1 और 3
- B. केवल 2 और 3
- C. केवल 1
- D. 1, 2 और 3

उत्तर: A. केवल 1 और 3

स्पष्टीकरण:

कथन 1 सही है: D2D टेक्नोलॉजी सैटेलाइट्स को मोबाइल डिवाइस से सीधे जोड़ने की सुविधा देती है, जिससे दूरस्थ क्षेत्रों में भी कनेक्टिविटी मिल सकती है।

कथन 2 गलत है: कई D2D सैटेलाइट टेक्नोलॉजी सामान्य स्मार्टफोन के साथ भी कार्य कर सकती हैं, यदि वे उपयुक्त बैंड सपोर्ट करते हों।

उदाहरण: Qualcomm के चिपसेट और SpaceX की Starlink/DIRECT-to-Cell सेवा।

कथन 3 सही है: भारत में Jio और Airtel जैसी कंपनियाँ इस क्षेत्र में स्टार्टअप्स (जैसे AST SpaceMobile, Skylo) के साथ सहयोग कर रही हैं।

वन नेशन, वन सब्सक्रिप्शन योजना



- **क्या है ONOS योजना?**
- 'वन नेशन, वन सब्सक्रिप्शन' (ONOS) एक सरकारी योजना है, जिसे हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है।
- **इसका मकसद है** – भारत के सभी शैक्षणिक और सार्वजनिक संस्थानों को वैज्ञानिक और शैक्षणिक जर्नल्स तक बराबर और मुफ्त डिजिटल पहुंच देना।

CABINET DECISION
25TH NOVEMBER, 2024

**One Nation
One Subscription**



- Cabinet approves **One Nation One Subscription** - Central Sector Scheme for providing country-wide access to scholarly research articles and journal publication
- Scheme to be administered through a simple, user friendly and fully digital process
- **Rs.6,000 crore** has been allocated for **One Nation One Subscription** for 3 calendar years viz **2025, 2026 and 2027**
- Benefits to be provided to all Higher Educational Institutions under the **Central or State Government** and **R&D Institutions of Central Government**



- इस योजना का उद्देश्य क्या है?
- विज्ञान, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, गणित (STEM) और सामाजिक विज्ञान जैसे क्षेत्रों में प्रकाशित ई-जर्नल्स और डेटाबेस का राष्ट्रीय लाइसेंस लेना।
- छोटे-बड़े सभी संस्थानों के शोधकर्ताओं को महंगे विदेशी जर्नल्स तक फ्री एक्सेस दिलाना।



वन नेशन, वन सब्सक्रिप्शन योजना



Daily Current News

- योजना की प्रमुख बातें
- डिजिटल एक्सेस:
- सब्सक्रिप्शन का पूरा प्रबंधन INFLIBNET (UGC का एक केंद्र) करेगा।
- निगरानी:
- ANRF (राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन) समय-समय पर योजना की प्रगति और उपयोग की समीक्षा करेगा।



वन नेशन, वन सब्सक्रिप्शन योजना



Daily Current News

- **प्रमुख प्रकाशक शामिल:**
- ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, कैम्ब्रिज, एल्सेवियर जैसे 30 बड़े पब्लिशर्स के 13,000 से ज्यादा जर्नल्स तक पहुंच।
- **सरकारी खर्च:**
- 2025 से 2027 के बीच इस योजना पर 6,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
- **कार्यान्वयन:**
- उच्च शिक्षा विभाग एक पोर्टल बनाएगा और जागरूकता फैलाने के लिए अभियान चलाएगा।





- इस योजना की ज़रूरत क्यों थी?
- महंगे सब्सक्रिप्शन:
- अच्छे जर्नल्स तक पहुंच पाने के लिए शोधकर्ताओं को लाखों रुपये खर्च करने पड़ते थे।
- शोषणकारी मॉडल:
- कम गुणवत्ता वाले जर्नल्स पैसे लेकर बिना जांच के शोध प्रकाशित करते हैं, जिससे शोध की गुणवत्ता गिरती है।





- **कॉपीराइट की दिक्कत:**
- विदेशी प्रकाशक कॉपीराइट लेकर लेखकों की सामग्री का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं।
- **छोटे संस्थानों की परेशानी:**
- टियर-2, 3 शहरों के कॉलेज और यूनिवर्सिटी इन जर्नल्स तक नहीं पहुंच पाते, जिससे शोध का स्तर गिरता है।





- इस योजना से होने वाले फायदे
- 1. सस्ती और समान पहुंच: पूरे देश के 8,300 से ज्यादा संस्थानों को लाभ मिलेगा।
- 2. शोध में बढ़ोत्तरी: चीन और दक्षिण कोरिया जैसे देशों की तरह भारत में भी वैज्ञानिक प्रकाशनों की संख्या बढ़ेगी।
- 3. विविधता को बढ़ावा: देशभर के शोधकर्ता किसी भी विषय पर आसानी से शोध कर पाएंगे।
- 4. राष्ट्रीय लक्ष्य को सहयोग: यह योजना भारत@2047 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करेगी।





- चुनौतियां क्या हैं?
- 1. ओपन एक्सेस का बढ़ता रुझान: अब 50% से ज्यादा शोध पहले से ही फ्री में उपलब्ध है।
- ऐसे में ONOS की उपयोगिता पर सवाल उठते हैं।
- 2. केवल बड़े जर्नल्स को लाभ: यह योजना केवल बड़े और विदेशी प्रकाशकों को लाभ दे सकती है, छोटे भारतीय जर्नल्स को नहीं।



- **3. कॉपीराइट का नुकसान:** लेखक अपना अधिकार खो देते हैं, जिससे उनकी सामग्री का मनचाहा इस्तेमाल हो सकता है।
- **4. डिजिटल समस्या:** छोटे शहरों में तेज इंटरनेट न होने से इसका पूरा लाभ नहीं मिल सकता।



वन नेशन, वन सब्सक्रिप्शन योजना



Daily Current News

- **आगे क्या किया जा सकता है?**
- **सस्ता समझौता:** सरकार को प्रकाशकों से बात करके 90-95% तक सब्सक्रिप्शन शुल्क में कटौती करानी चाहिए।
- **कॉमन लाइसेंस नीति:** सभी संस्थानों के हितों की रक्षा के लिए एक समान लाइसेंस समझौता बनाना चाहिए।

Subscription



वन नेशन, वन सब्सक्रिप्शन योजना



Daily Current News

- **ओपन एक्सेस को बढ़ावा:** भारतीय जर्नल्स को समर्थन देना चाहिए और शोधकर्ताओं को APC (प्रकाशन शुल्क) के लिए मदद मिलनी चाहिए।
- **डिजिटल संरचना मजबूत करनी चाहिए:** ताकि दूरदराज के क्षेत्रों तक भी यह योजना पूरी तरह पहुंच सके।

प्रश्न: 'वन नेशन, वन सब्सक्रिप्शन' (ONOS) योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह योजना भारत सरकार द्वारा अनुसंधान और शैक्षणिक संस्थानों को वैज्ञानिक शोध-पत्रों और जर्नल्स की सामूहिक पहुँच प्रदान करने के लिए शुरू की गई है।
2. इस योजना का उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों को महंगे विदेशी जर्नल्स की सदस्यता व्यक्तिगत रूप से लेने से मुक्त कराना है।
3. इस योजना को भारत के राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

- A. केवल 1 और 2
- B. केवल 3
- C. केवल 2 और 3
- D. 1, 2 और 3

उत्तर: A. केवल 1 और 2

स्पष्टीकरण:

कथन 1 सही है: ONOS योजना का उद्देश्य भारत के अनुसंधान और शैक्षणिक संस्थानों को प्रमुख अंतरराष्ट्रीय शोध जर्नल्स और प्रकाशनों की सेंट्रलाइज्ड सब्सक्रिप्शन के माध्यम से सामूहिक पहुँच प्रदान करना है।

कथन 2 सही है: इसका प्रमुख लक्ष्य उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए लागत कम करना और समान अवसरों को बढ़ाना है, ताकि सभी संस्थान शोध-सामग्री तक पहुँच बना सकें।

कथन 3 गलत है: इस योजना का राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय द्वारा प्रत्यक्ष क्रियान्वयन नहीं किया जा रहा है, बल्कि यह भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) तथा Ministry of Education के तहत विचाराधीन रही है।



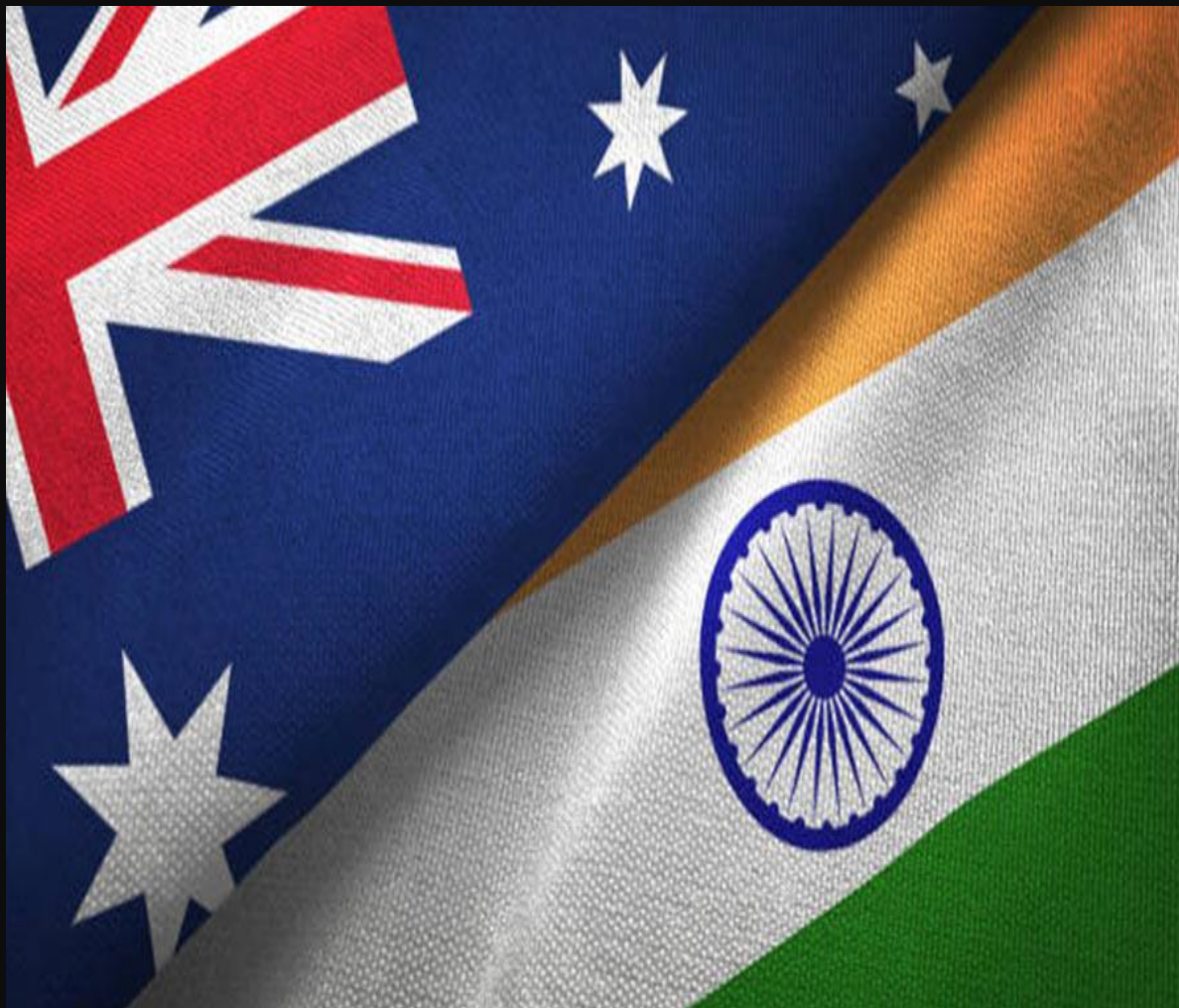
भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंध







- **भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंध: विस्तृत अध्ययन**
- **1. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और विकास**
- दोनों देश ब्रिटिश उपनिवेश के अंग रहे हैं और कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के सदस्य हैं।
- द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय सैनिकों ने ऑस्ट्रेलिया के साथ दक्षिण-पूर्व एशिया में युद्ध किया था।
- 1944 में भारत ने कैनबरा में उच्चायोग की स्थापना की।
- 1950 में ऑस्ट्रेलिया ने नई दिल्ली में अपना उच्चायोग खोला।



- **2. राजनयिक और राजनीतिक सहयोग**
- 2009: दोनों देशों के बीच Strategic Partnership की स्थापना।
- 2020: इसे Comprehensive Strategic Partnership (CSP) में बदला गया।
- **उच्च स्तरीय वार्ताएँ:**
- India-Australia Leaders' Virtual Summit (2020)
- India-Australia 2+2 Dialogue (विदेश और रक्षा मंत्रियों की बैठक)



- QUAD (Quadrilateral Security Dialogue) में सहयोग
- **3. रक्षा और सुरक्षा सहयोग**
- 2020 में Mutual Logistics Support Agreement (MLSA):
- दोनों देशों की सेनाएँ एक-दूसरे के सैन्य अड्डों का उपयोग कर सकती हैं।
- Malabar Exercise में ऑस्ट्रेलिया की पूर्ण भागीदारी (2020 से)
- Defence Science and Technology Collaboration
- समुद्री सुरक्षा (Maritime Domain Awareness) और आतंकवाद निरोधक सहयोग



- **4. आर्थिक और व्यापारिक संबंध**
- द्विपक्षीय व्यापार: वर्ष 2023-24: 25+ अरब डॉलर का व्यापार
- मुख्य वस्तुएँ: भारत से ऑस्ट्रेलिया: जैविक रसायन, आभूषण, वस्त्र, इंजीनियरिंग सामान
- ऑस्ट्रेलिया से भारत: कोयला, लोहा, तांबा, कृषि उत्पाद, शिक्षा सेवाएँ



- **प्रमुख समझौते:**
- ECTA (Economic Cooperation and Trade Agreement) – 2022
- 85% ऑस्ट्रेलियाई वस्तुओं पर भारत द्वारा शून्य शुल्क
- 96% भारतीय वस्तुएँ ऑस्ट्रेलियाई बाजार में शून्य शुल्क पर
- CECA (Comprehensive Economic Cooperation Agreement) – प्रस्तावित और वार्ता जारी



- **5. शिक्षा और संस्कृति**
- ऑस्ट्रेलिया में 1 लाख से अधिक भारतीय छात्र अध्ययन कर रहे हैं।
- **प्रमुख सहयोग:**
- Australia India Education Council (AIEC)
- नई Migration and Mobility Partnership Arrangement – छात्रों और पेशेवरों की आवाजाही के लिए



- **सांस्कृतिक आदान-प्रदान:**
- योग दिवस, बॉलीवुड फिल्म महोत्सव, भारतीय भोजन महोत्सव
- क्रिकेट और खेलों में गहरा जुड़ाव
- **6. ऊर्जा और जलवायु सहयोग**
- ऑस्ट्रेलिया भारत का प्रमुख कोयला और यूरेनियम आपूर्तिकर्ता है।
- Uranium Supply Agreement (2014): भारत को असैन्य परमाणु उपयोग हेतु यूरेनियम आपूर्ति।



- International Solar Alliance (ISA) में साझेदारी
- Hydrogen Energy Partnership: हरित हाइड्रोजन पर अनुसंधान और निवेश
- **7. प्रवासी भारतीय और जनसंपर्क**
- ऑस्ट्रेलिया में 8 लाख से अधिक भारतीय मूल के लोग (Australian Bureau of Statistics, 2023)
- भारतीय समुदाय शिक्षा, चिकित्सा, आईटी, और व्यवसाय में सक्रिय। नस्लीय हिंसा की कुछ घटनाओं पर भारत ने चिंता जताई है।



- **8. सहयोग के अन्य क्षेत्र**
- साइबर सुरक्षा (Cyber Security Dialogue)
- अंतरिक्ष अनुसंधान: ISRO और Australian Space Agency का सहयोग
- कृषि और जल प्रबंधन
- आपदा प्रबंधन और मानवीय सहायता (HADR Operations)

9. चुनौतियाँ



क्षेत्र	चुनौतियाँ
शिक्षा	नस्लीय हमले, वीजा नियमों में कठोरता
व्यापार	CECA वार्ता में विलंब
रणनीति	चीन पर दृष्टिकोण में सूक्ष्म अंतर
प्रवासन	Skilled migration के लिए कठिन प्रक्रियाएँ

प्रश्न: भारत-ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता (Comprehensive Economic Cooperation Agreement CECA) पहले ही पूर्ण रूप से लागू हो चुका है।
2. दोनों देश क्वाड (Quad) समूह के सदस्य हैं।
3. ऑस्ट्रेलिया, भारत का एक महत्वपूर्ण ऊर्जा साझेदार है, विशेषकर कोयला और लिक्विफाइड नेचुरल गैस (LNG) के मामले में।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

- A. केवल 2 और 3
- B. केवल 1 और 2
- C. केवल 2
- D. 1, 2 और 3

उत्तर: A. केवल 2 और 3

स्पष्टीकरण:

कथन 1 गलत है: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच CECA (Comprehensive Economic Cooperation Agreement) पर अभी वार्ता चल रही है, यह अभी तक पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ है। हालांकि, ECTA (Economic Cooperation and Trade Agreement) 2022 में लागू किया गया था, जो एक प्रारंभिक समझौता है।

कथन 2 सही है: भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों क्वाड (Quad) के सदस्य हैं, जिसमें अमेरिका और जापान भी शामिल हैं।

कथन 3 सही है: ऑस्ट्रेलिया, भारत को थर्मल कोयला, कोकिंग कोल और LNG की आपूर्ति करने वाला एक प्रमुख देश है। यह ऊर्जा सहयोग द्विपक्षीय संबंधों का एक अहम पहलू है।



भगवान बिरसा मुंडा



- **क्यों चर्चा में हैं?**
- 15 नवंबर 2024 को भारत ने भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में जनजातीय गौरव दिवस मनाया।
- इस अवसर पर पूरे देश में विभिन्न कार्यक्रमों और विकास योजनाओं का आयोजन किया गया।



- **जनजातीय गौरव दिवस क्या है?**
- शुरुआत: भारत सरकार ने 2021 में घोषित किया कि हर वर्ष 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा।
- **उद्देश्य:**
 - 1. बिरसा मुंडा की स्मृति में
 - 2. भारत के स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासी समुदायों के योगदान को सम्मान देने के लिए



- **भगवान बिरसा मुंडा: एक परिचय**
- जन्म: 15 नवंबर 1875, उलिहातू गांव (वर्तमान झारखंड)
- मृत्यु: 9 जून 1900 (ब्रिटिश पुलिस की हिरासत में)
- **मुख्य पहचान:**
- आदिवासी नेता, स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक "धरती आबा" (पृथ्वी के पिता) के रूप में विख्यात

भगवान बिरसा मुंडा



Daily Current News



- **संघर्ष:**
- ब्रिटिश शासन और जमींदारी प्रथा के खिलाफ
- आदिवासियों की जमीन और संस्कृति की रक्षा के लिए उलगुलान (विद्रोह) किया
- **2024 के समारोह की प्रमुख बातें**
- छत्तीसगढ़ में आयोजन: "माई भारत यूथ वॉलंटियर्स" के साथ "माटी के वीर पदयात्रा" कार्यक्रम का आयोजन हुआ।
- स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किए गए।



- आदिवासी योजनाओं का शुभारंभ: प्रधानमंत्री द्वारा 6,640 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास।
- योजनाएँ आदिवासी शिक्षा, स्वास्थ्य, जल आपूर्ति, और आवास को बेहतर बनाने पर केंद्रित थीं।



- प्रधान मंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (PM-JANMAN)
- उद्देश्य:
- विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना।
- मुख्य बिंदु:
- समयावधि: 2023-24 से 2025-26 तक (3 वर्ष)
- लाभार्थी: 75 PVTG समुदाय
- 18 राज्य और 1 केंद्रशासित प्रदेश

भगवान बिरसा मुंडा



Daily Current News



- **कुल बजट: 24,104 करोड़ रुपये**
- **समाविष्ट योजनाएँ: 9 मंत्रालयों की 11 योजनाएँ**
जैसे: प्रधानमंत्री आवास योजना (पक्के घर)
- **जल जीवन मिशन (शुद्ध पेयजल)**
- **सड़क योजना, स्वास्थ्य सेवाएँ, शिक्षा, पोषण आदि।**



- **वन धन विकास केंद्र (VDVKs)**
- आदिवासी समुदायों की आय बढ़ाने के लिए लघु वनोपज (Minor Forest Produce) आधारित उद्यमों को बढ़ावा दिया जाता है।
- स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से प्रशिक्षण और विपणन सहायता दी जाती है।



बिरसा मुंडा के योगदान

क्षेत्र	योगदान
सामाजिक	- बाल विवाह, अंधविश्वास और नशाखोरी के विरुद्ध जागरुकता फैलाना - आदिवासियों को जबरन ईसाई धर्मांतरण से बचाने का प्रयास
राजनीतिक	- ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष करना
धार्मिक	- आदिवासी धार्मिक पहचान को पुनर्जीवित करना - बिरसाइट धर्म की स्थापना, जिसमें एक ईश्वर की पूजा और पवित्रता पर बल दिया गया



- **परिचय:**
- मुंडा विद्रोह 1899-1900 के बीच बिहार (अब झारखंड) के क्षेत्र में आदिवासी मुंडा समुदाय द्वारा ब्रिटिश शासन, जमींदारों और मिशनरियों के अत्याचारों के खिलाफ किया गया एक महत्वपूर्ण जनजातीय आंदोलन था।
- इस विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया, जिन्हें आज "धरती आबा" (धरती के पिता) के नाम से जाना जाता है।



- **प्रमुख कारण:**
- 1. भूमि संबंधी शोषण: मुंडाओं की सामूहिक भूमि व्यवस्था ("खुंटकट्टी") को समाप्त कर दिया गया और जमींदारों, साहूकारों व ठेकेदारों को जमीनें सौंप दी गईं।
- 2. ईसाई मिशनरियों का प्रभाव: मिशनरियों ने पारंपरिक आदिवासी धर्म और संस्कृति को खत्म करने का प्रयास किया।
- 3. राजस्व नीति: ब्रिटिशों की लगान प्रणाली ने आदिवासियों को कर्ज में डुबो दिया।



- 4. वन कानून: परंपरागत जंगलों पर मुंडाओं के अधिकार खत्म कर दिए गए, जिससे उनका जीवनयापन संकट में पड़ गया।
- **बिरसा मुंडा का योगदान:**
- बिरसा मुंडा ने आदिवासियों को संगठित कर उन्हें उनके पारंपरिक अधिकारों के लिए जागरूक किया।
- उन्होंने एक धार्मिक और सामाजिक आंदोलन भी चलाया, जिसमें आदिवासियों को शराब, अंधविश्वास और ईसाई धर्म त्यागने के लिए प्रेरित किया।



- उनका नारा था: "अबुआ दिशुम, अबुआ राज" (हमारा देश, हमारा राज)।
- **विद्रोह की घटनाएँ:**
- 1899 में बिरसा मुंडा ने खुलकर विद्रोह का आह्वान किया। ब्रिटिश अधिकारियों, मिशनरियों और जमींदारों के खिलाफ कई हमले किए गए।
- जनवरी 1900 में डोमबाड़ी पहाड़ी पर ब्रिटिश सेना ने विद्रोहियों पर हमला किया।



- बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया और 9 जून 1900 को रांची जेल में संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो गई।
- **परिणाम:**
- यह विद्रोह भले ही सफल न रहा हो, परंतु इसने आदिवासी चेतना को जन्म दिया।
- ब्रिटिश सरकार को "छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908" लाना पड़ा, जिससे आदिवासियों की भूमि पर कुछ हद तक अधिकार सुरक्षित हुए।



Thank
you